रजिस्टर्ड नं० पी०/एम० एम०/14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 29 मार्च, 1988/9 चैत्र, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

शिमला-4, मार्च 28, 1988

संख्या 1-18/88-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1988 (1988 का विधेयक संख्यांक 3)

717-राजपत्र/88-29-3-88—1,240.

मूल्य: 20 पैसे ।

जो दिनांक 28 मार्च, 1988 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरः स्थापित हो गया है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

लक्ष्मण सिंह,
सचिव

1988 का विधेयक संख्यांक 3.

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1988

(विधान सभा में यथा पुरः स्थापित)

वित्तीय वर्ष 1985-86 में, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन के प्राधिकरण के लिए उपबन्ध करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1988 है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से 1985-86 वर्ष के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए 3,33,42,240 रुपए की अतिरिक्त राशि का प्राधिकरण ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग 3,33,42,240 रुपए (तीन करोड़, तेत्तीस लाख, ब्यालीस हजार, दो सौ चालीस रुपए) है, वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएगी ।

विनियोग ।

3. इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त, सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी।

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

1	2		3		
मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
			रु0	रु0	रु0
2	राज्यपाल और मन्त्रिपरिषद्	(राजस्व)	74,817	—	74,817
5	भू-राजस्व	(पूंजी)	21,800	—	21,800
9	चिकित्सा एव परिवार नियोजन	(पूंजी)	19,18,890	—	19,18,890
10	लोक निर्माण	(राजस्व)	1,75,33,855	—	1,75,33,855
13	भूमि तथा जल संरक्षण	(पूंजी)	10,12,679	—	10,12,679
17	सड़कें तथा पुल	(राजस्व)	51,23,491	—	51,23,491
		(पूंजी)	—	9,011	9,011
18	पूर्ति, उद्योग और खनिज	(राजस्व)	6,65,829	—	6,65,829
21	सामुदायिक विकास	(पूंजी)	92,925	—	92,925
23	खाद्य और पोषाहार	(राजस्व)	30,99,685	—	30,99,685
28	पर्यटन	(पूंजी)	1,86,568	—	1,86,568
33	वित्त	(राजस्व)	28,08,784	—	28,08,784
35	जन-जातीय विकास	(पूंजी)	7,93,906	—	7,93,906
		जोड़	3,33,33,229	9,011	3,33,42,240

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के खण्ड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए अनुदान और विनियोजन के अतिरिक्त किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त धन के विनियोजन का उपबन्ध करने हेतु पुर:स्थापित है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
28 मार्च, 1988

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग फ़ाईल नं0 फिन-ए-सी (2) 1/87]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1988 की विषय-वस्तु के बारें में सूचित किये जाने के पश्चात, भारत के संविधान क अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुर: स्थापित करन और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

[*Authoritative English text of the Himachal Pradesh Viniyog (Sankhya* 3) *Vidheyak*, 1988 (1988 *ka Vidheyak Sankhyank* 3) *as required under Clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

Bill No. 3 of 1988

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 1988

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the authorisation of appropriation of certain amount out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet the amount spent on certain services for the financial year 1985-86 *in excess of the amount authorised or granted for those services for that year.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1988.

Authorisation of a further sum of Rs. 3,33,42,240 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the year 1985-86.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 3,33,42,240 (three crores, thirty-three lakhs forty-two thousand, two hundred and forty rupees) shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the Schedule during the financial year 1985-86 in excess of the amount authorised or granted for these services and for that year.

Appropriation.

3. The sums deemed to have been authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year 1985-86.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2		3		
Number of Demand	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	*Charged* on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	74,817	—	74,817
5	Land Revenue	(Capital)	21,800	—	21,800
9	Medical and Family Planning	(Capital)	19,18,890	—	19,18,890
10	Public Works	(Revenue)	1,75,33,855	—	1,75,33,855
13	Soil and Water Conservation	(Capital)	10,12,679	—	10,12,679
17	Roads and Bridges	(Revenue)	51,23,491	—	51,23,491
		(Capital)	—	9,011	9,011
18	Supplies, Industries and Minerals	(Revenue)	6,65,829	—	6,65,829
21	Community Development	(Capital)	92,925	—	92,925
23	Food and Nutrition	(Revenue)	30,99,685	—	30,99,685
28	Tourism	(Capital)	1,86,568	—	1,86,568
33	Finance	(Revenue)	28,08,784	—	28,08,784
35	Tribal Development	(Capital)	7,93,906	—	7,93,906
		Total	3,33,33,229	9,011	3,33,42,240

STATMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 read with clause (1) of Article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure on account of expenses in excess of grants and appropriations for the financial year 1985-86.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA:
March, 28, 1988

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. A-C(2)1/87]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Bill, 1988 recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the aforesaid Bill in the Legislative Assembly.

शिमला-4, मार्च 29, 1988

संख्या 1-15/88-वि0 स0--हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1988 (1988 का विधेयक संख्यांक 2) जो दिनांक 29 मार्च, 1988 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुर:स्थापित हो गया है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रषित किया जाता है।

लक्ष्मण सिंह,
सचिव।

1988 का विधेयक संख्यांक 2.

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1988

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

वित्तीय वर्ष 1988-89 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धन-राशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1988 है । संक्षिप्त नाम ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धन-राशियां, जिनका योग 9,43,65,46,000 रुपये (नौ अरब, तैंतालीस करोड़, पैंसठ लाख, छियालीस हजार रुपये) है, संदत्त और उपयोजित की जाएं जिनका वित्तीय वर्ष 1988-89 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रभारों के संदाय को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा । हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से 1988-89 वर्ष के लिए 9,43,65,46,000 रुपये की राशि जारी करना ।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित करने के लिए प्राधिकृत धन-राशियों का उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजन किया जाएगा । विनियोग ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2		3		
मांग संख्या	सेवाएं एवं प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
			रुपये	रुपये	रुपये
1	विधान सभा और निर्वाचन	(राजस्व)	1,55,09,000	3,63,000	1,58,72,000
2	राज्यपाल और मन्त्रिपरिषद्	(राजस्व)	69,26,000	34,43,000	1,03,69,000
3	न्याय प्रशासन	(राजस्व)	3,36,81,000	71,84,000	4,08,65,000
4	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	20,49,87,000	42,61,000	20,92,48,000
		(पूंजी)	11,83,000	—	11,83,000
5	भू-राजस्व	(राजस्व)	11,30,39,000	—	11,30,39,000
		(पूंजी)	10,90,000	—	10,90,000
6	आबकारी और कराधान	(राजस्व)	4,70,44,000	—	4,70,44,000
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन	(राजस्व)	33,13,49,000	—	33,13,49,000
8	शिक्षा, खेलें तथा कला और संस्कृति	(राजस्व)	1,22,37,21,000	—	1,22,37,21,000
		(पूंजी)	5,26,19,000	—	5,26,19,000
9	चिकित्सा और परिवार कल्याण	(राजस्व)	38,92,58,000	—	38,92,58,000
		(पूंजी)	2,50,48,000	—	2,50,48,000
10	लोक निर्माण	(राजस्व)	46,10,92,000	—	46,10,92,000
		(पूंजी)	3,85,65,000	—	3,85,65,000
11	कृषि	(राजस्व)	32,55,03,000	—	32,55,03,000
		(पूंजी)	11,19,40,000	—	11,19,40,000
12	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	(राजस्व)	18,52,13,000	—	18,52,13,000
		(पूंजी)	14,26,54,000	—	14,26,54,000
13	भूमि और जल संरक्षण	(राजस्व)	11,53,52,000	—	11,53,52,000
		(पूंजी)	68,08,000	—	68,08,000
14	पशु पालन और दुग्ध विकास	(राजस्व)	8,88,19,000	—	8,88,19,000
		(पूंजी)	1,14,77,000	—	1,14,77,000
15	मत्स्य	(राजस्व)	94,62,000	—	94,62,000
		(पूंजी)	17,50,000	—	17,50,000
16	वन और वन्य जीवन	(राजस्व)	37,41,86,000	—	37,41,86,000
		(पूंजी)	1,57,76,000	—	1,57,76,000
17	सड़कें और पुल	(राजस्व)	16,84,43,000	—	16,84,43,000
		(पूंजी)	43,19,60,000	50,00,000	43,69,60,000
18	पूर्ति, उद्योग और खनिज	(राजस्व)	24,78,99,000	—	24,78,99,000
		(पूंजी)	3,53,14,000	—	3,53,14,000

1	2		3		
			रुपये	रुपये	रुपये
19	सामाजिक सुरक्षा, कल्याण (पोषाहार सहित)	(राजस्व)	16,36,08,000	—	16,36,08,000
		(पूंजी)	79,36,000	—	79,36,000
20	ग्रामीण विकास	(राजस्व)	19,11,69,000	—	19,11,69,000
		(पूंजी)	6,00,000	—	6,00,000
21	सहकारिता	(राजस्व)	4,46,73,000	—	4,46,73,000
		(पूंजी)	3,71,30,000	—	3,71,30,000
22	खाद्य और भण्डारण	(राजस्व)	3,71,04,000	—	3,71,04,000
		(पूंजी)	6,33,35,000	—	6,33,35,000
23	जल और विद्युत विकास	(राजस्व)	2,69,38,000	—	2,69,38,000
		(पूंजी)	44,36,00,000	--	44,36,00,000
24	लेखन सामग्री और मुद्रण	(राजस्व)	3,22,26,000	--	3,22,26,000
		(पूंजी)	3,60,000	--	3,60,000
25	सड़क, जल परिवहन और नगर विमानन	(राजस्व)	7,94,04,000	--	7,94,04,000
		(पूंजी)	9,40,10,000	--	9,40,10,000
26	पर्यटन और आतिथ्य संगठन	(राजस्व)	1,44,77,000	--	1,44,77,000
		(पूंजी)	1,17,20,000	--	1,17,20,000
27	श्रम और रोजगार	(राजस्व)	2,71,49,000	--	2,71,49,000
		(पूंजी)	31,75,000	--	31,75,000
28	जलपूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास	(राजस्व)	47,15,26,000	--	47,15,26,000
		(पूंजी)	17,86,55,000	--	17,86,55,000
29	वित्त	(राजस्व)	40,06,17,000	63,78,50,000	1,03,84,67,000
		(पूंजी)	--	67,87,80,000	67,87,80,000
30	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	(पूंजी)	3,26,20,000	--	3,26,20,000
31	जन-जातीय विकास	(राजस्व)	35,65,95,000	--	35,65,95,000
		(पूंजी)	16,33,71,000	--	16,33,71,000
		कुल जोड़ ..	8,09,96,65,000	1,33,68,81,000	9,43,65,46,000
		(राजस्व)	6,18,69,69,000	65,31,01,000	6,84,00,70,000
		(पूंजी)	1,91,26,96,000	68,37,80,000	2,59,64,76,000

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 1988-89 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला:
29 मार्च, 1988.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग फाइल सं0 फिन0 ए0 सी0 (1) 25/87]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1988 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

[*Authoritative English text of the Himachal Pradesh Viniyog No.* 2 *Vidheyak*, 1988 (1988 *ka Vidheyak Sankhyank* 2) *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

Bill No. 2 of 1988

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (No. 2) BILL, 1988

(As Introduced In the Legislative Assembly)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year, 1988-89.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradssh in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1988. Short title

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 9,43,65,46,000 (Nine hundred and forty-three crores, sixty-five lakhs and forty-six thousand rupees) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year, 1988-89 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule. Issue of a sum of Rs. 9,43,65,46,000 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the year 1988-89.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year. Appropriation.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2		3		
			Sums not exceeding		
Demand No.	Services and purposes		Voted by the Legislative Assembly	*Charged* on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha and Election	(Revenue)	1,55,09,000	3,63,000	1,58,72,000
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	69,26,000	34,43,000	1,03,69,000
3	Administration of Justice	(Revenue)	3,36,81,000	71,84,000	4,08,65,000
4	General Administration	(Revenue)	20,49,87,000	42,61,000	20,92,48,000
		(Capital)	11,83,000	—	11,83,000
5	Land Revenue	(Revenue)	11,30,39,000	—	11,30,39,000
		(Capital)	10,90,000	—	10,90,000
6	Excise and Taxation	(Revenue)	4,70,44,000	—	4,70,44,000
7	Police and Allied Organisations	(Revenue)	33,13,49,000	—	33,13,49,000
8	Education, Sports and Arts and Culture	(Revenue)	1,22,37,21,000	—	1,22,37,21,000
		(Capital)	5,26,19,000	—	5,26,19,000
9	Health and Family Welfare	(Revenue)	38,92,58,000	—	38,92,58,000
		(Capital)	2,50,48,000	—	2,50,48,000
10	Public Works	(Revenue)	46,10,92,000	—	46,10,92,000
		(Capital)	3,85,65,000	—	3,85,65,000
11	Agriculture	(Revenue)	32,55,03,000	—	32,55,03,000
		(Capital)	11,19,40,000	—	11,19,40,000
12	Irrigation and Flood Control	(Revenue)	18,52,13,000	—	18,52,13,000
		(Capital)	14,26,54,000	—	14,26,54,000
13	Soil and Water Conservation	(Revenue)	11,53,52,000	—	11,53,52,000
		(Capital)	68,08,000	—	68,08,000
14	Animal Husbandry and Dairy Development	(Revenue)	8,88,19,000	—	8,88,19,000
		(Capital)	1,14,77,000	—	1,14,77,000
15	Fisheries	(Revenue)	94,62,000	—	94,62,000
		(Capital)	17,50,000	—	17,50,000
16	Forest and Wild Life	(Revenue)	37, 1,86,000	—	37,41,86,000
		(Capital)	1,57,76,000	—	1,57,76,000
17	Roads and Bridges	(Revenue)	16,84,43,000	—	16,84,43,000
		(Capital)	43,19,60,000	50,00,000	43,69,60,000
18	Supplies, Industries and Minerals	(Revenue)	24,78,99,000	—	24,78,99,000
		(Capital)	3,53,14,000	—	3,53,14,000
19	Social Security, Welfare (including nutrition)	(Revenue)	16,36,08,000	—	16,36,08,000
		(Capital)	79,36,000	—	79,36,000
20	Rural Development	(Revenue)	19,11,69,000	—	19,11,69,000
		(Capital)	6,00,000	—	6,00,000

1	2		3		
			Rs.	Rs.	Rs.
21	Co-operation	(Revenue)	4,46,73,000	—	4,46,73,000
		(Capital)	3,71,30,000	—	3,71,30,000
22	Food and Warehousing	(Revenue)	3,71,04,000	—	3,71,04,000
		(Capital)	6,33,35,000	—	6,33,35,000
23	Water and Power Development	(Revenue)	2,69,38,000	—	2,69,38,000
		(Capital)	44,36,00,000	—	44,36,00,000
24	Stationery and Printing	(Revenue)	3,22,26,000	—	3,22,26,000
		(Capital)	3,60,000	—	3,60,000
25	Road, Water Transport and Civil Aviation	(Revenue)	7,94,04,000	—	7,94,04,000
		(Capital)	9,40,10,000	—	9,40,10,000
26	Tourism and Hospitality Organisation	(Revenue)	1,44,77,000	—	1,44,77,000
		(Capital)	1,17,20,000	—	1,17,20,000
27	Labour and Employment	(Revenue)	2,71,49,000	—	2,71,49,000
		(Capital)	31,75,000	—	31,75,000
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development	(Revenue)	47,15,26,000	—	47,15,26,000
		(Capital)	17,86,55,000	—	17,86,55,000
29	Finance	(Revenue)	40,06,17,000	63,78,50,000	1,03,84,67,000
		(Capital)	—	67,87,80,000	67,87,80,000
30	Loans to Government Servants	(Capital)	3,26,20,000	—	3,26,20,000
31	Tribal Development	(Revenue)	35,65,95,000	—	35,65,95,000
		(Capital)	16,33,71,000	—	16,33,71,000
	Grand Total	..	8,09,96,65,000	1,33,68,81,000	9,43,65,46,000
	(Revenue)	..	6,18,69,69,000	65,31,01,000	6,84,00,70,000
	(Capital)	..	1,91,26,96,000	68,37,80,000	2,59,64,76,000

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 1988-89.

VIRBHADR ASINGH,
Chief Minister.

SHIMLA:
The 29th March, 1988.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. A.C. (1) 25/87]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriaion (No. 2) Bill, 1988, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the said Bill by the Legislative Assembly.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।